PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Rajasthan Patrika, Jaipur
Monday 3rd August 2015, Page: 10
Width: 16.43 cms, Height: 14.56 cms, a4, Ref: pmin.2015-08-04.20.18

रेशम उद्योग की बदलेगी सूरत

स्थापित होंगे नए उपकरण व मशीन

आधुनिकीकरण की राह पर कर्नाटक रेशम उद्योग निगम

बेंगलूरु. विश्व प्रसिद्ध मैसूर सिल्क साड़ियां तैयार करने वाले कर्नाटक रेशम उद्योग निगम (केएसआईसी) की अधीनस्थ कंपनियां आधुनिकीकरण की राह पर हैं। अपनी स्थापना के सौ साल पूरे कर चुके केएसआईसी में सुधारों के लिए सरकार की मंजूरी मिल चुकी है।

केएसआईसी के अध्यक्ष डी बसवराज के अनुसार निगम द्वारा मैसूरु एवं टी नरसिंहपुरा में संचालित कारखानों से उत्पादित रेशमी सूत और रेशमी वस्त्रों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार ने उनके आधुनिकीकरण की मंजूरी दे दी है। दोनों ही कारखानों में आधुनिक उपकरण और नए मशीन लगाए जाएंगे।

इससे अपव्यय कम होगा और उत्पादन लागत घटेगी। मैसूरु कारखाने के आधुनिकीकरण पर जहां 3.6 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

वहीं टी. नरसिंहपुर कारखाने के आधुनिकीकरण पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नए मशीन लगाने का विचार साड़ियों की गुणवत्ता में सुधार के लिए है।

किसानों की आजीविका का साधन

उन्होंने कहा कि नए मशीनों को लगाए जाने से परिचालन में काफी अंतर आ जाएगा। दोनों कारखानों में रेशमी धागों और कपड़ों से रेशमी उत्पाद तैयार किया जाता है।

टी नरसिंहपुर कारखाने से कच्चे रेशमी धागों का उत्पादन होता है। इसे मैसूरु कारखाने में प्रसंस्करण और गुणवत्ता युक्त नए उत्पाद तैयार करने के लिए भेज दिया जाता है।

मैसूरु कारखाने में क्रेप्स, जरी और जार्जेट की साड़ियां तैयार की जाती हैं। इसका काफी फैला और बड़ा बाजार है। केएसआईसी के महाप्रबंधक सदानंद स्वामी ने बताया कि हर साल करोड़ों रुपए के कच्चे सिल्क खरीदे जाते हैं। कारखाने के जरिए रेशम उत्पादक सैकड़ों किसानों को आजीविका मिलती है।

हर साल 4.25 लाख मीटर रेशमी वस्त्र का उत्पादन

मैसूरु रेशम बुनाई कारखाना हर साल 4 लाख 25 हजार मीटर रेशमी कपड़े तैयार करता है। पिछले वर्ष कारखाने की आय 100 करोड़ रुपए थी। इस कारखाने का भवन 100 साल पुराना है। कारखाने के अंदर हथकरघा (हैंडलूम) की जगह पावरलूम ले चुके हैं। कंपनी ने जापान और यूरोप से आधुनिक मशीनों का आयात किया है। बुनाई, डिजाइनिंग और साड़ियों की रंगाई कुशल और मंझे हुए मैसूरु के कारीगर करते हैं।

हालांकि, अब साड़ियों पर प्रिंट कंप्यूटर के जरिए होने लगा है। प्रिंट करने वाले लोग मैसूरु की पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले हैं। हर महीने यहां 20 टन कच्चे रेशम का उपयोग होता है। प्रति 2.5 टन कच्चे रेशम से 30 हजार मीटर रेशम का उत्पादन होता है। कच्चा रेशम टी.नरसिंहपुर इकाई से आता है।

गुणवत्ता से समझौता नहीं करेगा निगम

मैसूरु सिल्क की मांग आज भी बरकरार है। इसकी वजह है गुणवत्ता वाले कोकून का उपयोग और कच्चे माल की ऊंची कीमतों के बावजूद गोल्ड जरी के साथ समझौता नहीं किया जाना।

ऊंची गुणवत्ता को कायम रखने के लिए कोकून शट्टलगट्टा और रामनगर से प्राप्त किया जाता है। कच्चे रेशम के हर लॉट को केंद्रीय रेशम बोर्ड और चेन्नई स्थित राष्ट्रीय परीक्षण घर में परखा जाता है।

शुरू में मैसूरु इकाई में दस करघा स्थापित किए गए थे। मांग के अनुसार दस और करघे लगाए गए। धीरे-धीरे क्षमता बढ़ती गई और आज 44 करघा इस कारखाने में लगे हुएहैं। इन्हें जापान और स्विट्जरलैंड से मंगाया गया है। वर्ष 198 0 में मैसूरु के इस रेशमी बुनाई कारखाने को केएसआईसी के सुपुर्द कर दिया गया जो कि राज्य सरकार का एक उपक्रम है। आधुनिकीकरण होने से इस इकाई की स्थिति और बदलेगी। साथ ही लोगों को गुणवत्तामूलक उत्पाद में और बदलाव दिखेगा। (का.सं.)

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Jagran, Delhi
Tuesday 4th August 2015, Page: 8
Width: 23.79 cms, Height: 19.26 cms, a3r, Ref: pmin.2015-08-04.28.57

जीएसटी के विकल्प की जरूरत

वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से फायदे कम नुकसान अधिक होने की आशंका जता रहे हैं डॉ. भरत झुनझुनवाला

मोदी सरकार के द्वारा झूठे अध्ययनों के आधार पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) को लागू करने के पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। 13वें वित्त आयोग ने जीएसटी का अध्ययन करने के लिए टास्क फोर्स गठित की थी। टास्क फोर्स में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फाइनेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर तथा सरकारी अधिकारियों को शामिल किया गया था। टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जीएसटी के कारण तमाम उत्पादित माल के दाम घटेंगे। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी। सही है कि माल के दाम में गिरावट आएगी। बिना रुकावट माल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा सकेगा। टैक्स के संबंध में विवाद कम होंगे। चुंगी से छुटकारा मिलेगा। अर्थव्यवस्था चलेगी, जैसे अच्छा मोबिल आयल डालने से गाड़ी अच्छी तरह चलती है। यह प्रभाव सर्वव्यापी होगा। अमीर की 5000 रुपये की डिजाइनर शर्ट तथा आम आदमी की सूरत की 250 रुपये की साड़ी, दोनों के दामों में गिरावट आएगी। परंतु दूसरे कारणों से आम आदमी द्वारा खपत की तमाम वस्तुओं के दाम में वृद्धि होगी।

वर्तमान में आम आदमी तथा अमीर द्वारा खपत की जाने वाली वस्तुओं पर अलग-अलग दर से टैक्स वसूला जा रहा है। जैसे किसी राज्य द्वारा आम आदमी के मोटे कपड़े, साइकिल के टायर तथा साधारण मोबाइल फोन पर टैक्स कम तथा रेडीमेड कपड़े, कार के टायर तथा स्मार्ट फोन पर टैक्स अधिक वसूला जा रहा है। जीएसटी के लागू होने के बाद इन सभी माल पर एक ही दर से टैक्स वसूला जाएगा। फलस्वरूप आम आदमी द्वारा खपत की जाने वाली वस्तुओं के दाम कई प्रतिशत बढ़ेंगे। आम आदमी पर कुल प्रभाव नकारात्मक पड़ेगा। टास्क फोर्स ने इस पहलू को नजरअंदाज किया है और बिना विचार किए कह दिया है कि जीएसटी से गरीब को राहत मिलेगी।

वर्तमान में छोटे उद्योगों को एक्साइज ड्यूटी में राहत मिलती है। व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि छोटे उद्योगों के लिए यह छूट अति महत्वपूर्ण है। 1.5 करोड़ तक के उत्पादन पर इन्हें टैक्स नहीं देना होता है। इस छूट के कारण छोटे उद्योग खड़े रह सके हैं। टास्क फोर्स ने कहा है कि इस छूट को समाप्त कर देना चाहिए। फलस्वरूप छोटे उद्योग पर टैक्स का भार बढ़ेगा। बड़े उद्योगों का वे सामना नहीं कर सकेंगे और बंद हो जाएंगे। इन्हीं उद्योगों द्वारा अधिकतर रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनके बंद होने से लाखों श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन टास्क फोर्स ने माना है कि अर्थव्यवस्था में एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है।

ऐसे झूठे मानकों पर यह अध्ययन किया गया है जैसे बच्चे को खाना न दिया जाए और यह मान लिया जाए कि वह खाना खा चुका है। तथापि स्वीकार करना होगा कि बड़े उद्योगों के द्वारा बाजार में सस्ता माल उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार आम आदमी पर दो विपरीत प्रभाव पड़ेंगे। छोटे उद्योगों को मिल रही छूट के समाप्त होने के कारण उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जबकि जीएसटी के कारण उत्पादित माल के मूल्य में मामूली गिरावट आएगी और उन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। टास्क फोर्स ने एक्साइज ड्यूटी की छूट को समाप्त किए जाने से आम आदमी पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को अनदेखा किया है।

टास्क फोर्स ने कहा है कि जीएसटी के लागू होने के कारण व्यापार करना सरल हो जाएगा। श्रमिक की उत्पादकता बढ़ेगी। जैसे वर्तमान में श्रमिक द्वारा बनाए गए माल पर एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स तथा चुंगी अलग-अलग वसूल की जाती है। इन झंझट में माल की लागत अनायास ही बढ़ जाती है। जैसे बाजार में एक टीशर्ट 100 रुपये की बिक रही है। मान लीजिए इस पर इन टैक्सों का बोझ तथा इनसे निपटने में लगे समय एवं घूस इत्यादि का भार 15 रुपये पड़ता है। श्रमिक द्वारा उत्पादित माल की कीमत 85 रुपये रह जाती है। जीएसटी लागू होने के बाद टैक्सों का यह बोझ घटकर 14 रुपये रह जाएगा। तदानुसार श्रमिक द्वारा उत्पादित माल की कीमत बढ़कर 86 रुपये रह जाएगी।

इस आधार पर टास्क फोर्स ने निष्कर्ष निकाला है कि जीएसटी के लागू होने से श्रमिकों के वेतन में एक प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह निष्कर्ष पूरी तरह गलत है। श्रमिक के वेतन उसके द्वारा उत्पादित माल के मूल्य से नहीं, बल्कि श्रम बाजार में श्रमिकों की उपलब्धता से निर्धारित होता है। टैक्सी मालिक द्वारा इंडिका को बेचकर इनोवा खरीद ली जाए तो ड्राइवर के वेतन में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि इनोवा चलाने को बाजार में पर्याप्त संख्या में ड्राइवर उपलब्ध हैं। जीएसटी से केवल कंपनी के मालिक का लाभ बढ़ेगा जैसे इनोवा के मालिक का लाभ अधिक होता है। टास्क फोर्स ने बिना किसी आधार के मान लिया है कि इनोवा के ड्राइवर के वेतन इंडिका के ड्राइवर से ज्यादा होते हैं। इसी प्रकार नेशनल काउंसिल फॉर अपलाइड इकोनामिक रिसर्च द्वारा एक अध्ययन किया गया है। इन फर्जी अध्ययनों के आधार पर मोदी सरकार कह रही है कि जीएसटी प्रणाली आम आदमी के लिए लाभप्रद होगी, जबकि वस्तुस्थिति बिल्कुल विपरीत है।

जीएसटी के इन नकारात्मक पहलुओं के बावजूद इसमें गुण है कि खपत पर टैक्स बढ़ेगा। देश की आर्थिक उन्नति के लिए जरूरी है कि हम निवेश अधिक मात्रा में करें। इसके लिए खपत कम करनी होगी। जीएसटी के माध्यम कुल टैक्स ज्यादा वसूला जाएगा जोकि खपत पर टैक्स होगा। परंतु आम आदमी और अमीर द्वारा की जाने वाली खपत में भेद करना जरूरी है। सही पालिसी है कि अमीर द्वारा खपत किए जाने वाले माल जैसे कार, फ्लैट स्क्रीन टीवी एवं स्मार्ट फोन पर टैक्स बढ़ाया जाए और आम आदमी द्वारा खपत किए जाने वाले माल जैसे साइकिल टायर, सूरत की साड़ी, माचिस इत्यादि पर टैक्स घटाया जाए। लेकिन जीएसटी का सिद्धांत है कि सभी माल पर एक ही दर से टैक्स लगाया जाएगा, जिससे व्यवस्था सरल और विवाद रहित हो। इसलिए जीएसटी से आम आदमी द्वारा खपत की तमाम वस्तुओं के दाम में वृद्धि होगी।

मोदी सरकार को जीएसटी के विकल्पों पर विचार कराना चाहिए। ऐसी टैक्स व्यवस्था बनानी चाहिए जो कि सरल हो और साथ-साथ अमीर पर टैक्स का भार अधिक पड़े। बताते चलें कि विश्व के 160 देशों ने जीएसटी लागू किया है। इससे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन देशों के आम आदमी की हालत अच्छी नहीं है। मोदी जैसे कर्मठ शासक के लिए यह संभव है कि वह भेड़ चाल से हटकर ऐसी टैक्स व्यवस्था बनाएं जो आर्थिक कुशलता के साथ-साथ सामाजिक मानदंड पर भी सही उतरे।

(लेखक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)

response@jagran.com

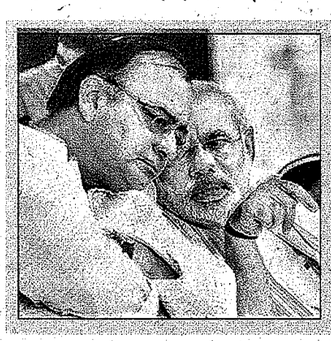

नई व्यवस्था की कसौटी

मोदी सरकार को जीएसटी के विकल्पों पर विचार करना चाहिए। ऐसी टैक्स व्यवस्था बनानी चाहिए जो कि सरल हो और साथ-साथ अमीर पर टैक्स का भार अधिक पड़े

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Deccan Herald, Delhi
Tuesday 4th August 2015, Page: 17
Width: 20.56 cms, Height: 17.52 cms, a4r, Ref: pmin.2015-08-04.33.136

Haute trends

To cater to all your fashion needs

The Amazon India Couture Week 2015 was an eye-opener for all the fashionistas who keep a tab on the latest fashion trends. The exquisite collection by some of the well-known names of the fashion industry, during the star-studded week, provided a peep into the latest fashion trends. Some of the most celebrated actors of Bollywood walked the ramp flaunting the fine creations of these fashion gurus. *Metrolife* gets you a round-up of the trends you need to know about and flaunt this season.

For all the ladies out there, the AICW 2015 was a lot about floral-inspired collections of anarkalis, sari gowns, sari lehengas in your wardrobe. Textured fabrics, voluminous gown-like silhouettes that could be worn as lehengas, trails of exquisite silk -- lending the woman an air of majesty are also finding place in the fashion scene this season. The colour palette too is as exciting as ever ranging from metallic silver and antique gold to rich burgundy, old rose pink, pearl grey and coffee brown. Details such as three-dimensional embroidery, mushroom-flower and bird motifs in delicate threadwork are what make the attire even more appealing.

Dreamy ethereal cuts, artfully draped gown saris, ravishingly sensual gowns structured seductively to enhance the contours of the body, balanced by elegantly innovative pantsuits are a way to flaunt the feminine yet modern woman.

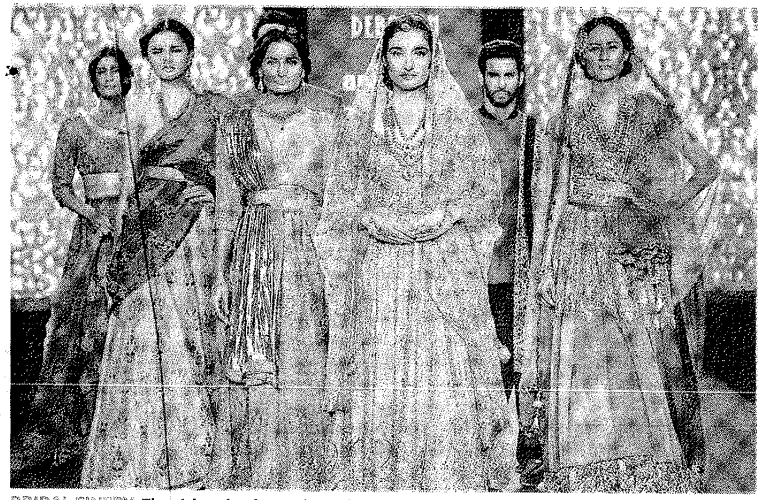

BRIDAL FINERY **Floral-inspired creations dominated collections at the fashion week.**

For those who are preparing for the most special day of their life, there is something very special in the scintillating hand-crafted embroideries and dazzling Preciosa crystals dramatic capes and robes, sheer billowy jackets, regal cloaks and lehengas that make rich statements in regal clothing. Tempered in hues of ivory and beige, burnished golds and velveteen ruby, the ensembles hark back to the time of Maharajas and Maharanis.

You can also opt for something quite different on your wedding day by flaunting the look of a rebel bride. This collection is for the 'cool laid-back bride' and her entourage! The collection reflects the amalgam of different elements, which make for a memorable wedding onboard a luxury yacht. There are well-detailed masterpieces, complexity of forms and its multiple interpretations of elements on fabrics which outline the nature of cross cultures of the world, the boat, sea foams, fiery pieces of the coral reef, starfish and shells, the stark beams of the sun, textured sand; these are the various forms implemented in each opus.

Gulbagh's lush floral theme with red rose maang tikkas and marigold all around will be a perfect look to flaunt. Made out of fabrics like velvets, silk, and cotton, they ensure you make a style statement, and how! Floral-inspired collection of anarkalis, sari gowns, sari lehengas are some options for luxury weddings design.

Clutches, wallets and handbags are every girl's favourite accessory. When it comes to dressing fashionably, women complete their look with a perfect handbag. But this season we suggest you to go with some spiked clothes and wallet that garner you more eyeballs.

For men, bandhgalas and Nehru jackets are always a good choice to make. Highlighted by the beauty of traditional Indian embroidery, interpreted in a modern way, the choice can make one stand apart among all. With works of *zari, zardozi, badla ka kaam*, fine *resham ka kaam,* Parsi embroidery, teamed with shawls, can make one rethink their stand on couture clothing. Try some printed pants to club with the traditional wear.

Replete with structured jackets, trench coats and waistcoats, in hues of blue and black with a touch of intricate embroidery are another choice. Vintage glasses, bow ties and neck ties will add a hint of dandy to your collection of couture clothing.

Puja Gupta

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Financial Express, Delhi
Tuesday 4th August 2015, Page: 6
Width: 23.27 cms, Height: 25.03 cms, a3, Ref: pmin.2015-08-04.25.53

Make-in-India

For whom and at what cost?

Quality institutions, state-of-the-art infrastructure and efficient allocation of resources will be crucial

Of the many simmering slogans coined by the NDA government, "Make in India" is the most important as it promises to make India an important investment destination. However, like most other slogans, it is important to be clear about what has to be achieved and how. After all, Jawaharlal Nehru too strived to make in India by erecting high protective barriers. The policy completely ignored the interests of the consumers who had to put up with products of inferior quality at high costs. We departed from the strategy in 1991 because, it was not sustainable. Therefore, the slogan should have a different connotation not merely in terms of the tapestry, but also in terms of the real content.

Making India an important investment destination requires a systematic approach and strategy involving both policies and institutions. This requires the existing systems and processes to undergo significant changes to remove the structural rigidities and to create an accommodating ecosystem. The distributional coalitions that have deeply entrenched in the system will not easily allow such structural changes. A clear understanding on the part of the policy makers of what needs to be done to create a favourable ecosystem is necessary. This requires clarity, appropriate strategy and its communication with the people.

Operationalising of Make-in-India entails the Indian economy being internationally competitive, which requires the efficient use of existing resources and creating a favourable climate for achieving technological progress. Creating such an ecosystem calls for a combination of reforms to change the character and quality of institutions, provide state-of-the-art infrastructure and get the prices right to achieve efficient allocation of resources. Given the nature of federal polity and the fact that in a number of areas the states have important roles to perform, the policy and institutional changes will have to encompass both the Union and states. The Union government will have to work out strategies to carry the states in this long journey.

The most important intervention by the government is to change the character and quality of institutions. Admittedly, labour laws have been a binding constraint in promoting labour intensive industrialisation and the Union government's initiative in giving a greater role to the states is the best way forward. The pernicious effect of labour laws has led to declining fortunes of labour intensive industries like textiles and leather in which India has a comparative advantage. With labour becoming expensive in China, India can reclaim its lost ground. The labour laws rather than protecting the interests of labour have caused slow growth of employment and more particularly, organised sector employment in India.

A critical component of institutional restructuring is administrative reform. The second Administrative Reforms Commission has made useful recommendations, but surely, in a situation where bureaucracy is the most influential interest group, the tyranny of status quo will continue. Ensuring accountability and rewarding performance and making appointments on the basis of competence are the need of the hour. Bureaucrats never fade; virtually every regulatory system has been captured by the retired bureaucrats and competence has not always been the criterion in these appointments. The vitiation in the ease of doing business is exemplified by the functioning of the taxman. Not much has changed since the NDA government has taken over to change the attitude of tax administration.

Much as we have decried the licence-permit raj, this continues to pose impediments in various ways at all levels of government. The number of bureaucratic clearances required for every initiative from the Union, state and local levels are numerous. Courts do not resolve disputes within a reasonable time period and in the absence of an effective redressal mechanism, people are forced to take sub-optimal decisions. Protection of life and property is the basic function of the state and basic prerequisite for taking investment decisions. The Union government has to take a lead, though reforms encompass all levels of government.

M GOVINDA RAO

Many of the initiatives relating to Make-in-India require coordinated calibration of reform by both Union and state governments. It is also important that the required reforms get bi-partisan support

A lot has been written about the infrastructure deficit in the country. The investment in infrastructure projects stuck for one reason or another is estimated at over 8% of GDP. The cobweb needs to be cleared. The land acquisition issue is stuck in the political logjam; there are no easy solutions and the industry will have to work around it. The major problem in the power sector is the disconnection between the policies relating to generation and distribution. Despite several rounds of reforms based on bailouts to discoms, political interference and ineffective regulation have continued to paralyse the sector. The promise of recapitalisation of public sector banks may provide some financial room, but this is not going to solve the structural problems in the financial sector. The most important initiative needed is to step up public investment in infrastructure. Although the low volume of budgeted investment at the Union level is a matter of concern, the government has done well to front load capital expenditures. Better revenue collections from indirect taxes too point towards a possibility of enhanced investment spending. It is important to come out with an acceptable model concession agreement for PPPs to move forward in this area. Private investment clamours for low interest rate which implies that the fiscal deficit should be contained. In this environment, increase in public investment is possible only when the tax-GDP ratio increases. The GST reform promises much, but with compromises and distortions, one is not sure how much it will deliver. Indeed, it is necessary to view GST reform as a process, not a big bang reform.

A major structural problem constraining productivity in India is the control on prices. Even after 24 years of liberalisation, prices of many goods and services are determined through administered fiat rather than by demand and supply. Controls on prices have distorted the resource allocation at macro and micro levels and has proliferated subsidies. Administered interest rate on provident funds places a floor on the reduction in interest rates. Pre-empting a large proportion of household sector's savings for public spending distorts the structure of interest rates. Overvalued exchange rate hurts the export sector. We cannot distort cane prices, and then increase import duties on sugar to protect the sugar lobby and persuade increased proportion of blending ethanol in petrol to consume sugar sticks. Subsidising irrigated water results in the farmers adopting water intensive crops even when that is not appropriate. Subsidising electricity results in depletion of underground water. Subsidising urea results in the distorted consumption of fertilisers and soil salinity. The examples can be multiplied.

Indeed, many of the initiatives relating to Make-in-India require coordinated calibration of reform by both Union and state governments. It is also important that the required reforms get bi-partisan support. Forging consensus and securing support cannot be achieved through confrontationist strategy. The opposition has nothing to lose by opposing and it is here the ruling party has the primary responsibility to adopt a conciliatory approach to build consensus. Building hot and cold will not certainly help the cause of reform to Make-in-India.

The author is emeritus professor, NIPFP, and non-resident senior fellow, NCAER, and advisor, Takshashila Institution. E-mail: mgrao48@gmail.com

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Amar Ujala, Delhi
Tuesday 4th August 2015, Page: 12
Width: 25.19 cms, Height: 19.28 cms, a3r, Ref: pmin.2015-08-04.36.77

चीन में मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ती लागत के कारण कुछ टेक्सटाइल कंपनियां बांग्लादेश, भारत, वियतनाम जैसे कम लागत वाले देशों का रुख कर रही हैं। कई मामलों में तो इस पलायन को स्वयं चीन ने ही बढ़ाया है।

चीन का घटता दबदबा

पच्चीस वर्ष पहले नि मेइजुआन चीन के हांगझोऊ शहर की एक विशाल कपड़ा फैक्टरी में कताई मशीनों पर काम करके हर महीने 19 डॉलर कमाती थीं। अब साउथ कैरोलिना में बीते अप्रैल में खुले कीर समूह के कॉटन मिल में नि अमेरिकी श्रमिकों को उसी काम का प्रशिक्षण दे रही हैं, जो वह करती थीं।

पूर्व के कम लागत वाले देशों में कभी बड़े पैमाने पर सस्ते में कपड़ा तैयार करने वाले उत्पादक अब अमेरिका में अपनी फैक्टरियां खोल रहे हैं। कभी कम और ज्यादा लागत वाले देशों के बीच जो सुस्पष्ट विभाजन रेखा थी, उस हकीकत को खत्म कर देने का यह एक ज्वलंत उदाहरण है, जिसके बारे में एक दशक पहले कम ही लोगों ने सोचा होगा।

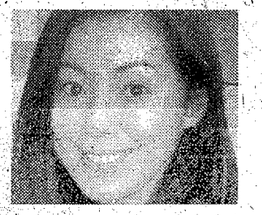

हाइरोको तबुची

लेख पर अपनी राय हमें यहां भेजें
edit@amarujala.com

वर्षों से बढ़ती मजदूरी, बिजली की ऊंची कीमत और परिवहन की बढ़ती लागत के साथ-साथ रुई के आयात पर सरकार द्वारा तय की गई सीमा के चलते चीन में वस्त्र उत्पादन एक गैर लाभप्रद उद्यम बन गया है। जबकि इसी दौरान अमेरिका में उत्पादन लागत अपेक्षाकृत ज्यादा प्रतिस्पर्धी हुई है। लैंकास्टर काउंटी में, जहां इंडियन लैंड स्थित है, कीर को कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार लोग मिले। साथ ही, वहां सस्ती और प्रचुर जमीन के अलावा किफायती ऊर्जा है। वहां भारी सब्सिडी पर रुई भी उपलब्ध है।

अमेरिका में काउंटी से लेकर राज्य और संघीय सरकार के राजनेताओं में मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित रोजगार को वापस लाने के लिए कीर को अनुदान और कर में छूट देने की होड़ लगी है, जिसके बारे माना जाता था कि यह हमेशा के लिए खत्म हो गया।

अमेरिका के नेतृत्व में एक व्यापक प्रशांत व्यापार समझौते की संभावना ने भी, जिसमें चीन शामिल नहीं है, चीनी धागा निर्माता कंपनियों को अमेरिका में अपने पांव पसारने के लिए प्रेरित किया है, ताकि ऐसा न हो कि आकर्षक अमेरिकी बाजार से वे वंचित रह जाएं। कीर की 21.8 करोड़ डॉलर की स्पिनिंग मिल रुई से काते धागों को पूरे एशिया के वस्त्र निर्माताओं को बेचता है। हालांकि कीर अब भी अधिकांश धागे की कताई

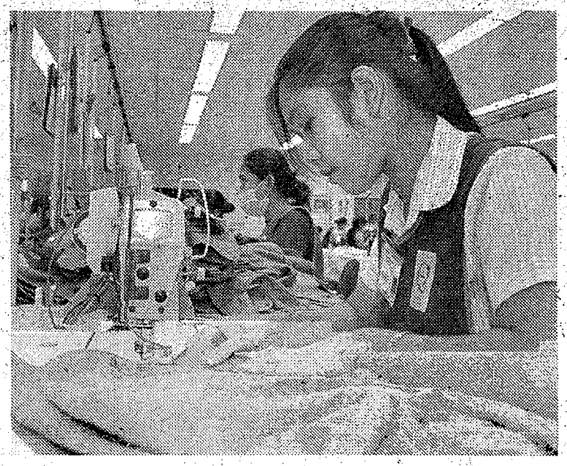

चीन में ही करता है और कच्चा माल अमेरिका से मंगाता है, लेकिन धीरे-धीरे इसमें परिवर्तन आ रहा है।

कीर के अमेरिका में आने का कारण क्या है? हाल ही में अमेरिका के दौरे पर आए कीर के चेयरमैन झु शैनक्विंग ने इसका जवाब दिया कि प्रोत्साहन, जमीन, व्यावसायिक माहौल और सस्ता श्रम इसकी प्रमुख वजह है। वह आगे कहते हैं, चीन में धागा निर्माण उद्योग घाटे में चल रहा है, जबकि अमेरिका में स्थिति अलग है।

1970 के दशक की शुरुआत में जबसे वाशिंगटन और बीजिंग के बीच व्यावसायिक रिश्ते फिर से कायम हुए, अमेरिका ज्यादातर भारी व्यापार घाटे में रहा, क्योंकि सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान और अन्य चीनी वस्तुओं की खरीद में अमेरिकियों ने अरबों डॉलर गंवा दिए। पर बढ़ती श्रम लागत और ऊर्जा कीमतों के कारण मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चीन की प्रतिस्पर्धी क्षमता खत्म हो रही है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के अनुसार, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चीन में मजदूरी पिछले एक दशक में तीन गुना बढ़ी है। वर्ष 2004 में जो मजदूरी 4.35 डॉलर प्रति घंटे थी, वह पिछले वर्ष अनुमानतः 12.47 डॉलर प्रति घंटे हो गई। जबकि अमेरिका में इसी क्षेत्र में मजदूरी 2004 से 30 फीसदी से भी कम बढ़ी है और वह 22.32 डॉलर प्रति घंटा है। हालांकि अमेरिका में इसकी भरपाई प्राकृतिक गैसों की कम कीमत, सस्ते कपास और सब्सिडी से हो जाती है।

अमेरिका की तुलना में चीन में धागे की उत्पादन लागत 30 फीसदी ज्यादा है। बोस्टन कंसल्टिंग के एक वरिष्ठ साथी ने बताया कि हर कोई समझता है कि चीन हमेशा सस्ता रहेगा, लेकिन चीजें कल्पना से भी ज्यादा तेजी से बदल रही हैं। चीन में मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ती लागत के कारण कुछ कंपनियां बांग्लादेश, भारत, वियतनाम जैसे कम लागत वाले देशों का रुख कर रही हैं। कई मामलों में तो इस पलायन को स्वयं चीन ने ही बढ़ाया है, जो आक्रामक तरीके से अपनी मैन्युफैक्चरिंग का आधार कहीं और स्थापित करना चाहता है।

न्यूयॉर्क स्थित रिसर्च कंपनी रोडियम ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के वर्षों में अमेरिका ने इन पलायन करने वाली कंपनियों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। 2004 से 2014 के बीच चीनी कंपनियों ने अमेरिका में नई परियोजनाओं एवं अधिग्रहण पर 46 अरब डॉलर का निवेश किया है। इनमें से ज्यादातर निवेश पिछले पांच वर्षों में हुआ है। पर ऐसा नहीं है कि अमेरिका के वस्त्र उद्योग में सिर्फ चीन से ही निवेश हो रहा है। पिछले वर्ष भारत की एक प्रमुख वस्त्र निर्माता कंपनी श्रीवल्लभ पित्तई ग्रुप ने जॉर्जिया के सिल्वानिया में सात करोड़ डॉलर का निवेश किया, जो पिछले चार दशकों में इस क्षेत्र का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है।

साउथ कैरोलिना में कीर के आगमन का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता था। वर्ष 2007 में स्पिंग्स इंडस्ट्रीज ने, जिसकी कॉटन मिल एक समय दुनिया में सबसे बड़ी थी, जब यहां अपना आखिरी प्लांट बंद किया था, तब से कारीगरों की एक पीढ़ी अपना रोजगार खो चुकी है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार घटने का लाभ यह हुआ है कि लेंकास्टर काउंटी जैसी जगहों में लोग कम मजदूरी पर काम करने को तैयार हैं। वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने पाया है कि साउथ कैरोलिना जैसी जगहों में यूनियनें भी नहीं हैं।

हालांकि अमेरिका आकर कीर ने जोखिम भी उठाया है। डॉलर के मजबूत होने से अमेरिका में भी उत्पादन लागत बढ़ रही है। इसके अलावा एरिजोना और कैलिफोर्निया में पानी की कमी से कपास का उत्पादन प्रभावित हो सकता है, कपास पर दी जाने वाली सब्सिडी पर तो अभी से खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा दो संस्कृतियों का फर्क भी दिखता है। नि अमेरिकी कामगारों की सुस्ती पर शिकायत करती हैं। उनके मुताबिक, चीन में सुस्त कामगारों के वेतन रोक दिए जाते हैं, लेकिन अमेरिका में लोगों को अनुशासित करना मुश्किल है। हालांकि नि को उम्मीद है कि धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा।

© 2015 The New York Times news and syndicate

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Business Line, Delhi
Tuesday 4th August 2015, Page: 17
Width: 27.87 cms, Height: 14.04 cms, a3r, Ref: pmin.2015-08-04.48.102

Price crash pushes sericulture farmers towards suicide

Raw silk duty cut triggers sharp fall

HANGING BY A THREAD

VISHWANATH KULKARNI
Bengaluru, August 3

Unable to deal with mounting debts amidst diminishing returns from his three-acre farm, Siddaramu, a sericulture farmer in his mid-fifties at Abburdoddi near Channapatna, committed suicide recently in his silkworm rearing house.

The trigger for this unfortunate incident was the crash in silk cocoon prices and the issuance of recovery notice by the bank, says Chandramma, his wife.

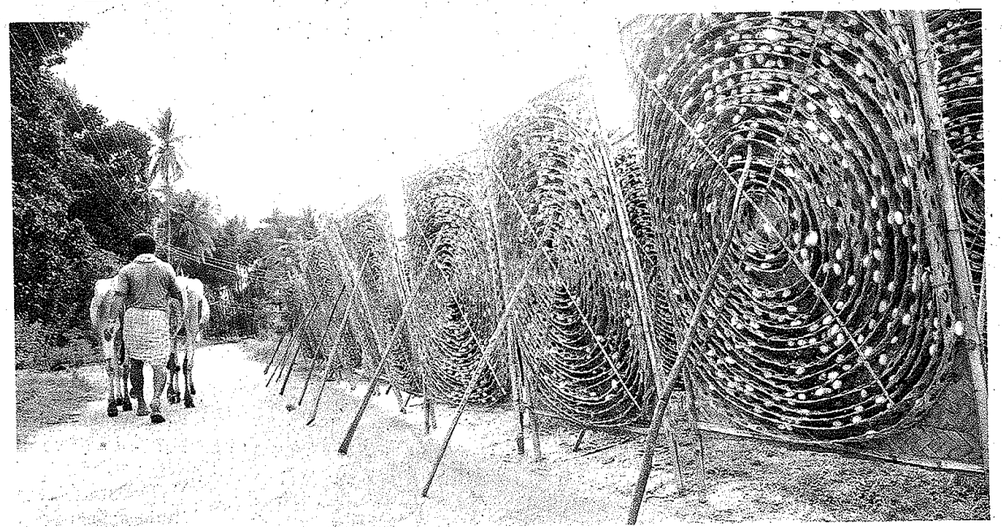

Red, red silk A view of *Chandrikes*, the make-shift platforms made from bamboo and coconut leaves on which the silk worms are placed to form cocoons, in the interiors of Channapatna taluk in Ramanagara district, Karnataka. GRN SOMASHEKAR

Other crops too failed

Siddaramu, like many other small and mid-sized farmers in the region, practiced multi-cropping, and to his bad luck the alternative crops such as maize and coconut have also suffered in recent years.

While mite infestation and declining water levels have hit the coconut plantations, maize prices have been bearish over past couple of years on excess supplies. "He had raised about ₹3 lakh as loan from the bank, part of which was used for sinking a borewell that failed. Also, a couple of lakhs were raised through hand loans," said Chandramma.

Siddaramu's suicide is not an isolated case of small farmers succumbing to the growing financial distress in the region.

In neighbouring Mandya, the sugar bowl of South Karnataka, over three dozen farmers, some of whom practiced sericulture have taken to committing suicide, which has reached epidemic proportions in the State.

"Ten of the 11 farmers who committed suicide in Ramanagara district in recent months practiced sericulture," said C Puttaswamy, a farmer leader. "The situation is very grave. The Government should formulate both short and long term measures to protect the silk worm growers," said Puttaswamy, an office bearer of Reshme Belagarara Hitarakshana Samiti.

Troubles for the sericulture farmers started intensifying over past three months ever since the Centre reduced the customs duty on raw silk imports to 10 per cent from the earlier 15 per cent, after which prices of both cocoons and the domestically produced raw silk have crashed.

Customs duty cut

Prices of the cross breed (CB) cocoons have dropped from an average of ₹267 per kg in April to around ₹148 in May only to recover later to ₹226 in early August, while the bivoltine variety have slumped from an average of ₹311 to around ₹237 in the same period.

The minimum price for CB variety fell to as low as ₹120/kg. In 2014-15, the average price for CB stood at ₹274, while for bivoltine it was ₹285 a kg.

Growers say the prices are much below the production cost estimated between ₹265 and ₹350, depending on the variety.

State's support price

Following a spate of protests and highway blockages by the silkworm rearers across key producing regions, the Karnataka government intervened and announced a support of ₹30 a kg over and above the auction price for the cross breed cocoon, while for the superior bivoltine variety, the support price has been fixed at ₹50.

Also, the State has set up a technical expert committee to study the current crisis, fix the cost of production for cocoons and recommend measures for the revival and stability of the sector.

The committee is expected to submit its report soon. Karnataka accounts for about two thirds of the raw silk produced in the country.

"The Centre should immediately restore the customs duty to 15 per cent and set up a revolving fund of ₹500 crore to intervene as and when the price falls below a threshold," said C Narayanaswami, Chairman of Silk Association of India, an outfit representing the entire chain of growers and reelers.

Farmers switch over

Dejected over the recent price crash, farmers are not keen in continuing with sericulture and are looking at alternatives such as vegetables.

There have been stray instances of farmers uprooting mulberry plantations across the key growing districts of Kolar, Ramanagaram and even Chikkaballapur.

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Business Line, Delhi
Tuesday 4th August 2015, Page: 18
Width: 6.13 cms, Height: 5.27 cms, a4, Ref: pmin.2015-08-04.48.118

Cotton flat on limited buying

Rajkot, August 3

Cotton prices traded unchanged on limited demand from domestic mills. *Kapas* or raw cotton remained unchanged on slow ginning demand. Moreover, weak export demand and expected higher carryover also weighed on the prices. Gujarat Sankar-6 cotton was at ₹33,500-34,200 per candy of 356 kg. About 1,500 bales (of 170 kg) arrived in Gujarat and 2,500 bales arrived in India. *Kapas* went for ₹900-925 per 20 kg in various mandis of Gujarat. Gin delivery *kapas* stood at ₹925-935. Cottonseed was flat at ₹425-450. OUR CORRESPONDENT